

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 21 जुलाई, 2020

विषय:—मै0 फैन्डस ऑटोमोबाईल्स के नाम से ग्राम तालिबाबाद, परगना रुड़की जिला—हरिद्वार में शोरूम एवं सर्विस सेन्टर खोलने हेतु 0.3134 है0 भूमि क्य की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—317/जि0भ०व्य0सहा0/2019, दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 तथा पत्र संख्या—620/जि0भ०व्य0सहा0/2020 (विविध), दिनांक 09 जून, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 फैन्डस ऑटोमोबाईल्स के नाम से ग्राम तालिबाबाद, परगना रुड़की जिला—हरिद्वार में शोरूम एवं सर्विस सेन्टर खोलने हेतु 0.3134 है0 भूमि क्य की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य-में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 फैन्डस ऑटोमोबाईल्स के नाम से ग्राम तालिबाबाद, परगना रुड़की जिला—हरिद्वार में शोरूम एवं सर्विस सेन्टर खोलने हेतु 0.3134 है0 भूमि क्य की अनुमति उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अध्यादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2019 की धारा—154(2)(ख) में निहित व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जर्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा—154(4)(3)(V) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- 1— केता धारा—129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2— केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (शोरूम एवं सर्विस सेन्टर खोलने) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होगा।

- 3— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 5— शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 6— इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 7— इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग निर्धारित प्रयोजन (शोरूम एवं सर्विस सेन्टर खोलने) के लिए ही किया जायेगा।
- 8— भूमि क्रय करने के उपरान्त निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान क्षेत्र के सक्षम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- 9— आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10— जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।
- 11— सम्बन्धित खातेदारों द्वारा बैंक ऋण अदा न किये जाने की दशा में सम्बन्धित इकाई द्वारा बैंक ऋण अदा किया जायेगा, के सम्बन्ध में शपथ-पत्र जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।
- 12— सम्बन्धित इकाई द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 13— किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 14— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 15— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों प्राप्त कर ली जायेगी।
- 16— सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनोजी०टी०) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 17— सम्बन्धित इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 18— सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 19— जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3— कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या—4७२/xviii(ii)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— मै0 फैन्डस ऑटोमोबाईल्स, रेवले रोड़, ज्वालापुर, हरिद्वार।
- 5— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपरसचिव।